Programme — Coarse Cereals (ICDP—Coarse Cereals) is being implemented in six States, namely, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Sikkim.

Statement

Production of Jowar during 1992-93 to 1994-95

(in Thousand tonnes)

State	1992-93	1993-94	1994-95
Andhra Pradesh	908.7	872.6	682.7
Bihar	2.3	2.8	2.6
Gujarat	323.6	280.1	191.6
Haryana	47.0	25.0	30.0
Karnataka	1925.9	1895.2	1612.9
Kerala	2.7	3.0	2.9
Madhya Pradesh	1555.2	1269.2	783.0
Maharashtra	6687.6	5976.2	4580.8
Orissa	11.8	15.8	16.8
Punjab	0.1	0.3	0.3
Rajasthan	411.5	160.5	273.1
Tamil Nadu	486.2	486.2	605.8
Uttar Pradesh	436.7	422.6	409.4
West Bengal	0.3	0.2	0.2
Dadra & Nagar Haveli	0.6	0.5	0.5
Delhi	5.3	4.7	4.7
ALL INDIA	12805.5	11414.9	9197.3

Marketing of Formulations

*398. SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the names of the two major Indian and two major multinational companies who are marketing the formulations based on Flucconazole, Felodipine. Trimetazidine Hcl. Roxithromycin, Cisplatin, Zidoudine, Cyclosporin and the price at which each is being marketed;

(b) since when each is being marketed; and

(c whether it is a fact that there is a wide difference in each of the brand of the same bulk drug, if so, the reasons and steps taken to bring the prices uniform by reducing the higher prices in the interest of consumers?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (c) These are non-scheduled formulations and a large number of them are being marketed by various companies like Mfc.

CIPLA, M/s. Torrent, *M/s.* Hoechst, M4. Astra IDL etc. These being .non-scheduled formulations their prices are not fixed by the Government but by the companies taking into account various factors operating in the market.

कृषि –उत्पादन के बाद आवश्यक तकनीकों का

उपयोग न किए जाने के कारण खाद्यान्नों का बेकार हो जाना

*399. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **:**

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादकों द्वारा कृषि-उत्पादन के बाद आवश्यक तकनीकों का उपयोग न किए जाने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न बेकार चले जाते है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बेकार हो जाने वाले इन खाद्यान्नों की मात्रा का कोई नुकसान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इनके मूल्य के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का नुकसान होता है;

(घ) क्या सरकार ने देश की परिस्थितियों के अनुसार कोई अनुकूल तकनीक विकसित करने हेतु कोई प्रयास किए है ताकि देश में खाद्यान्नों की इस प्रकार होने वाली हानि को रोका जा सके; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) देश में खाद्यान्नों के उत्पादकों द्वारा फसल कटाई के बाद की आवश्यक तकनीकों के उपयोग न किए जाने के कारण देश में खाद्यान्नों के बेकार होने के बारे में कोई ठोस अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह अनुमान है कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन की लगभग 2-3 प्रतिशत मात्रा फसल कटाई के बाद की खराब तकनीकों के कारण बेकार हो जाती है।

तिलहनों का उत्पादन

*400 **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या गत कुछ वर्षो से देश में तिलहनों का उत्पादन 200 से 200 लाख टन के बीच ही स्थिर रहा है और क्या यह मात्रा देश की आवश्यकता से बहुत कम है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में तिलहन की खेती हेतु प्रयुक्त भूमि विश्व के अन्य तिलहन उत्पादक देशों की तुलना में बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में तिलहन उत्पादकता की दर विश्व की उत्पादकता दर से बहुत कम है; और

(ड) यदि हां, तो विश्व उत्पादकता दर की तुलना में देश मे प्रति हैक्टेयर तिलहन को कितनी उपज होती है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ख) गत 5 वर्षो के दौरान तिलहनों का उत्पादन निम्न प्रकार था :-

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1990-91	186.1
1991-92	185.0
1992-93	201.06
1993-94	214.95
1994-95	214.17

1996-97 के लिए तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 23 मिलियन मीटरी टन है, जो योजना आयोग द्वारा आंकी गयी मांग पर आधारित है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि सन 2000 ईसवी तक 26 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ तिलहनों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ड) भारत में तिलहनों की उत्पादकता वर्ष 1993 के दौरान 1034 कि0 ग्राम प्रति हैक्टेयर की विश्व औसत की तुलना में 799 कि0 ग्राम प्रति हैक्टेयर है।